

एक पखवाड़े में भी नहीं बन पाई हार्डवेयर चौक की सड़क

- महज 50 मीटर सड़क बनाने के लिए खर्च हो रहे 32 लाख -काम के नाम पर पंद्रह दिन में लाल डस्ट ही डाली गई



फरीदाबाद (मजदूर मोर्चा) शहर के तेज विकास के लिए गठित किया गया फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) भी ब्रॉड और सुस्त विभागों की तरह काम कर रहा है। हार्डवेयर चौक की महज पचास मीटर सड़क की मरम्मत का काम पंद्रह दिन में भी पूरा नहीं कराया जा सका है।

शहर को प्याली चौक, बाटा चौक, बीके और सोहना रोड से जोड़ने वाला हार्डवेयर चौक बीते चार साल से जर्जर हालात में है। काफी समय से शहरवासी इस चौक की मरम्मत कराए जाने की मांग कर रहे थे। एफएमडीए ने इस चौक पर मैस्टिफ एस्फाल्ट (तारकोल की मोटी परत) बिछाकर यातायात सुगम करने का निर्णय लिया था।

महज पचास मीटर से भी कम बनने वाली इस सड़क का खर्च 32 लाख रुपये आंका गया है। काम के नाम पर 24 मार्च को लाल डस्ट का ढेर वहाँ लगा दिया गया। मरम्मत के नाम पर यही डस्ट दो तीन बार डलवाई जा चुकी है, लेकिन नियमित पानी का छिड़काब नहीं कराए जाने के कारण यह डस्ट उड़कर नष्ट हो रही है। आधुनिक मरम्मतों से अधिकतम दो से ढाई घंटों में मैस्टिफ एस्फाल्ट की परत बिछाई जा सकती है लेकिन एक पखवाड़ा बीतने के बाद भी सड़क ज्यों की त्यों है।

इन हालात को देखते हुए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त रकम भी खर्च हो जाए और सड़क भी ज्यों की त्यों पड़ी रह जाए, और फिर नए बजट की मांग खड़ी कर दी जाए।

डीसी की गाड़ी बिगड़ी तो सड़क बनाने की सुध आई

फरीदाबाद (मजदूर मोर्चा) सेक्टर 15 व 15 ए की विभाजक सड़क जो 15 ए की पुलिस चौकी से शुरू होकर जिमखाना क्लब तक जाती है, का नव निर्माण शीघ्र शुरू होने की बात चली है। करीब डेढ़ किलो मीटर लम्बी यह सड़क पूर्णतया जर्जर हो चुकी है। जगह-जगह बने खड़ों में आये दिन आम लोगों की गाड़ियां टूटती रही तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछले दिनों जब डीसी की गाड़ी भी ऐसे किसी खड़े में जाकर टुकी तो इस सड़क को बनाने की सुध आई।

विदित है कि डेढ़ किलो मीटर लम्बी इस सड़क पर डीसी के अलावा सेशन जज, एडीसी व कई अन्य बड़े अधिकारियों के आवास हैं जो नित्य प्रायः इस सड़क से होकर अपने कार्यालयों को जाते हैं। बाकी जनता की बात तो छोड़िये, जिसे के इन उच्चतम अधिकारियों के नित्य प्रति आवागमन के बावजूद इस सड़क पर ध्यान न देना सरकार की काहिली का एक उदाहरण है। इस सड़क के जर्जर होने का पहला कारण तो इसमें लगा घटिया माल व टूसरा कारण बरसाती पानी का लगातार खड़े रहना है। कहने को तो बरसाती पानी की निकासी के लिये लाइन डाली गई थी लेकिन वह केवल कागजों तक ही सीमित होकर रह गई लगती है।

अब इस सड़क को करीब आठ करोड़ की लगत से तारकोल की बजाय सीमेंट से बनाया जायेगा। इतना ही नहीं दो लेन वाली इस सड़क को चार लेन का बनाने के साथ-साथ फुटपाथ व साइकिल ट्रैक भी बनाने की बात कहीं जा रही है। बरसाती पानी की निकासी के लिये पहले से बनी जो लाइन गायब हो चुकी है उसे फिर से बनाया जायेगा। इसके द्वारा पानी की निकासी हो पायेगी या नहीं, यह तो समय ही बतायेगा। रही बात साइकिल ट्रैक की, तो उसे समझने के लिये करीब तीन साल पहले 18 लाख की लागत से बने उस साइकिल ट्रैक को देखा जा सकता है जो बाटा मोड़ से कच्चहरी होते हुए बाइपास तक जाता है। आज यह साइकिल ट्रैक कहीं ढूँढ़ने से भी नजर नहीं आता।

सेक्टरों की योजना बनाने वाले योजनाकार को शायद इनी समझ नहीं थी कि उसके द्वारा रखी गई सड़कों की चौड़ाई पर्याप्त नहीं रहेगी। इसलिये अब चौड़ाई बढ़ाने के लिये सड़कों के किनारे खड़े वृक्षों की बलि चढ़ाई जायेगी, जैसे कि सेक्टर 14 व 17 की विभाजक एवं बाइपास को हाइवे से जोड़ने वाली सड़क के वृक्ष साफ कर दिये गये हैं। 'हूडा' के इन आधुनिक योजनाकारों से वे योजनाकार कहीं अधिक समझदार थे जिन्होंने 1948 में एनआईटी की योजना बनाते समय विभाजक सड़कों की चौड़ाई 200 फीट व भीतरी सड़कों की चौड़ाई 100 फीट तक रखी थी। यह बात अलग है जो राजनेताओं में अवैध कब्जे करा कर उन सड़कों को संकरा कर दिया।

आठ माह पूर्व हुई गुड़िया की हत्या को लेकर डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन मुजेसर पुलिस ने दर्जनों प्रदर्शनकारियों को जाने से रोका

फरीदाबाद (मजदूर मोर्चा) गत वर्ष रक्षावधन के दिन 12 वर्षीय गुड़िया के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। घटना थाना मुजेसर के लगभग सामने रेलवे लाइन के साथ बसी आजाद नगर कॉलोनी की है।

यह जघन्य वारदात न केवल शहर में बढ़ते अपराध का द्योतक है बल्कि पीएम मोदी के उस स्वच्छता एवं 'खुले में शौच से मुक्त' अभियान की भी पौल खोलता है जिसके नाम पर मोदी सरकार ने विशेष टैक्स के जरिये जनता से अरबों-खरबों रुपये बसूले थे। करीब दो वर्ष पूर्व झूट बोलने में माहिर मोदी ने भारत को 'खुले में शौच से मुक्त' घोषित कर दिया था। यहाँ के नगर निगम ने शौचालय बनाने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च दिखा कर फ़ाइलों का पेटा भर दिया था। जनता को मुंह चिढ़ाते टूटे-फूटे एवं खंडहर शौचालय जगह-जगह देखे जा सकते हैं।

शहर की सैकंडों मजदूर बस्तियों में रहने वाली 8-10 लाख की आबादी जिस तरह से खुले में शौच जाने को मजबूर है, उसी तरह आजाद नगर कॉलोनी वासी भी रेलवे लाइन के किनारे शौच करने को मजबूर हैं। जाहिर है कि इस काम के लिये रात के अंधेरे में जाना ही उचित समझा जाता है। इसी अंधेरे का 'लाभ' उठा कर गुड़िया भी शौच के लिये गई थी जो कभी लौट कर न आ सकी, आ सका तो केवल उसका क्षति-विक्षत शव। आज तक इस केस का कोई अपराधी पकड़ा नहीं जा सका। कर्वाई के नाम पर पुलिस ने कॉलोनी वासियों पर भी खूब जम कर ढंडा घुमाया था।

वारदात के दिन से लेकर अभी तक



विभिन्न मजदूर एवं सामाजिक संगठनों द्वारा कई बार धरने प्रदर्शन किये जा चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक किसी अपराधी का पकड़ा जाना तो दूर, शौचालयों की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है। टूटे-फूटे व खंडहर शौचालय आज भी ज्यों की त्यों जनता को मुंह चिढ़ा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि शासन-प्रशासन को जनता की कोई परवाह नहीं है। हां, प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल तक जाने से रोकने में पुलिस अपना पूरा जोर लगा देती है। हर बार की तरह इस बार भी मुजेसर पुलिस ने उन चार ऑटो-रिक्षाओं को हिरासत में ले लिया था जिन में लद कर प्रदर्शनकारी डीसी कार्यालय जा रहे थे। हिरासत में लिये गये मजदूरों द्वारा हल्ला-गुल्ला करने पर उन्हें कुछ घटों बाद छोड़ दिया गया था।

इसी मसले को लेकर दिनांक पांच

मंझावली पुल एक दशक में भी बने या न बने, मीडिया चर्चा में बने रहना चाहिये अब दिसंबर 2023 तक पूरा करने का वायदा

फरीदाबाद (मजदूर मोर्चा) 15 अगस्त 2014 को केन्द्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी के हाथों पुल का शिलान्यास कराने के लिये स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गुजर ने बहुत ही भारी-भरकम मजमा वहाँ जुटाया था। उस वक्त शायद पुल का निर्माण इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि इसके नाम पर लाखों की भीड़ जुटाना। केन्द्रीय सत्ता पर काबिज होने के बाद अगला निशाना हरियाणा की सत्ता पर काबिज होना था, उसी के लिये प्रोपेरेंट्स के तौर पर वह नौटकी की गई थी।

प्रोपेरेंट्स को असरदार बनाने के लिये, पुल के बनने से जनता को होने वाले फायदों का खूब बढ़-चढ़ कर ढोल पीटा गया था। फायदों का यह ढोल न भी पीटा जाता तो भी सारी जनता को यह मालूम है कि दिल्ली से घूम कर नौएडा जाने की अपेक्षा इस पुल के जरिये जाने से उन्हें समय और धन की भारी बचत होगी।

उस वक्त कुछ लोगों ने कहा था कि इस पुल का शिलान्यास करीब बीस-पचास वर्ष पूर्व तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री राजेश पायलट ने भी किया था, इसके जवाब में भाजपा नेताओं ने कहा था कि वे नकली शिलान्यास नहीं करते, पुल को दो साल में चालू करके दिखा देंगे। भाजपाइयों की कार्यशैली की पूरी समझ रखते हुए मजदूर मोदी ने उसी वक्त यह प्रकाशित कर दिया था कि दो साल में पुल चालू करना तो दूर इसकी डीपीआर भी बना दें तो बड़ी बात होगी। हुआ भी वही, दो साल में डीपीआर नहीं बनी और नौ साल में पुल भी नहीं बना। लेकिन पुल के मुद्दे को मीडिया में जिंदा रखने के लिए कृष्ण पाल हर दूसरे-तीसरे महीने कोई न कोई शोशा छोड़ते आ रहे हैं।

अब यह कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2023 पुल का काम पूरा होने की डेडलाइन रखी गई है। मौका मुख्यालय आदि आदि तो बनाए जा सकते हैं लेकिन आम जनता की जरूरतों के लिए इस तरह का पुल बनाने में इनकी कोई विशेष सुचि नहीं है।